



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]
No. 53]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2009/चैत्र 23, 1931
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2009/CHAITRA 23, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2009

सं. टीएमपी/49/2008-जीटीआईपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा० लि० के मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च, 2009 के बाद के लिए विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/49/2008-जीटीआईपीएल

गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लि०

... आवेदक

आदेश

(मार्च, 2009 के 27वें दिन पारित)

यह मामला गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लि० (जीटीआईपीएल) से उसके दरमान के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. अक्टूबर, 2008 में जीटीआईपीएल से प्राप्त प्रस्ताव प्रशुल्क मामला रूप में पंजीकृत किया गया था और निर्धारित सामान्य विचार-विमर्श प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की गई थी।

3. अब, जीटीआईपीएल ने अपने पत्र दिनांक 6 मार्च, 2009 द्वारा इस प्राधिकरण को निम्नलिखित संप्रेषित किया है :

- (i) वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप सितम्बर, 2008 के बाद थुपट में काफी कमी आई है। वर्ष 2009, 2010 और 2011 के लिए कोई उपयुक्त परिमाण अनुमान लगाना कठिन हो रहा है।
- (ii) जनवरी 2009 और फरवरी 2009 के वास्तविक थुपट पर विचार करते हुए, वर्ष 2009 के लिए थुपट का अनुमान अक्टूबर, 2008 के प्रशुल्क प्रस्ताव में 13,95,030 टीईयू पर अनुमानित थुपट की तुलना में

11,00,000 टीईयू परिगणित किया गया है। थुपट में कटौती का प्रोद्भूत होने वाले व्यय पर तदनुरूपी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि लागत का प्रमुख हिस्सा अचल प्रकृति का है। 11,00,000 टीईयू प्रहस्तन के आधार पर तैयार किया गया आय/लागत विवरण वर्ष 2009 के लिए प्रचालन आय के प्रतिशत रूप में 27 प्रतिशत घाटा दर्शाता है।

(iii) प्रशुल्क, यदि आर्थिक मंदी के इस समय में निर्णीत किया जाता है तो विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और गैर-अनुमानित मात्राएं सही तस्वीर पेश नहीं कर पाएंगी क्योंकि प्रशुल्क की वैधता तीन वर्षों के लिए होगी। घाटा स्थिति के आधार पर प्रशुल्क में किसी वृद्धि से भूस्वामी पत्तन के लिए भी राजस्व को प्रभावित करते हुए मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना मुश्किल होगा।

(iv) जीटीआईपीएल वर्ष 2009 के अंत तक ही वर्ष 2010 और 2011 के लिए कंटेनर थुपट और वित्तीय स्थिति का उपयुक्त अनुमान लगाने और सही तौर पर बताने की स्थिति में होगा।

(v) चूंकि जीटीआईपीएल द्वारा अक्टूबर 2008 में अपने प्रस्ताव दाखिल करने के समय से आर्थिक परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है और इस स्थिति में प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में हो रही मुश्किलों पर विचार करते हुए, जीटीआईपीएल अपना प्रस्ताव दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 को वापस लेना चाहता है।

(vi) मौजूदा दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2009 तक विस्तारित किया जाए।

4. जीटीआईपीएल के दरमान की समीक्षा पहले से देय है। यह प्राधिकरण इसके प्रशुल्क की समीक्षा के लिए अक्टूबर, 2008 में जीटीआईपीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर औपचारिक कार्यवाही पहले ही शुरू कर चुका है। इसलिए, इसे संबद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात् ही कार्यवाहियों को पूरा करना उपयुक्त होगा। वैसे, यह प्राधिकरण जीटीआईपीएल द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 को वापस लेने की इस स्थिति में जीटीआईपीएल के अनुरोध को स्वीकार

करने के लिए प्रवृत्त नहीं है। यदि ऐसा जरूरी हो जाता है तो जीटीआईपीएल को एक अवसर दिया जाएगा कि वह अपने द्वारा बताई गई बदली परिस्थितियों को सही प्रकार से दर्शाने के लिए इसके प्रस्ताव दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 को अधुनातन करने का अवसर दिया जाएगा।

5. तथ्यांश यह प्रविष्टि जीटीआईपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून, 2009 तक अथवा इसके द्वारा अक्टूबर, 2008 में दाखिल किए गए जीटीआईपीएल के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करने के लिए प्रवृत्त है।

6. मार्च, 2008 के प्रस्तुत दिशा-निर्देशों का खंड 2.13 जीटीआईपीएल केवल 31 दिसम्बर, 2008 तक जीटीआईपीएल के वारतदिक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करने के लिए लागू होगा क्योंकि अगस्त, 2008 में जीटीआईपीएल के प्रस्तुत का अनुमान लगाने के निर्धारण के प्रयोजन के लिए सुविचारित वित्तीय स्थिति के अनुमान 31 दिसम्बर, 2008 तक थे।

यदि 1 जनवरी, 2009 के बाद स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से कोई अतिरिक्त आंग्रेशेष प्रकट होता है तो इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान ऐसा अतिरिक्त आंग्रेशेष मार्च, 2009 के दिशा-निर्देशों के खंड 2.13 के संदर्भ के बिना पूर्णतः समाप्त किया जाएगा।

7. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समय विचार-विमर्श के आधार पर यह प्रविष्टि जीटीआईपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून, 2009 तक अथवा इसके द्वारा अक्टूबर, 2008 में दाखिल जीटीआईपीएल के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, दरमान का निर्णय लेता है।

अरविन्द कुमार, सदस्य

[विज्ञापन III/4/143/08-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2009

No. TAMP/49/2008-GTIPL.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Gateway Terminals India Pvt. Ltd., beyond 31st March, 2009 as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

NO. TAMP/49/2008-GTIPL

Gateway Terminals India Private Ltd. ... Applicant

ORDER

(Passed on this 27th day of March, 2009)

This case relates to a proposal from the Gateway Terminals (India) Private Ltd. (GTIPL) for revision of its Scale of Rates.

2. The proposal received from the GTIPL in October, 2008 was registered as a tariff case and processed following the usual consultation process prescribed.

3. Now, the GTIPL vide its letter dated 6th March, 2009 has conveyed to this Authority, *inter alia*, the following :

- (i) There is a steady fall in the throughput after September, 2008 as a result of global economic recession. It is difficult to make any reasonable volume projections for the years 2009, 2010 and 2011.
- (ii) Considering the actual throughput of January, 2009 and February, 2009, the estimate of throughput for the year 2009 works out to 11,00,000 TEUs as compared to the throughput projected at 13,95,030 TEUs in the tariff proposal of October, 2008. The reduction in the throughput does not have corresponding effect in the expenditure to be incurred since major portion of the cost is fixed in nature. The income / cost statement drawn up based on handling 11,00,000 TEUs shows 27% deficit as a percentage of operating income for the year 2009.
- (iii) The tariff, if decided at this time of economic turmoil, fluctuating foreign exchange rate and unpredictable volumes will not reflect a correct picture since the tariff will have a validity for three years. Any increase in the tariff based on deficit position will make it difficult to retain the existing customers affecting the revenue for land lord port also.
- (iv) GTIPL will be in a position to estimate reasonably and accurately the container throughput and the financial position for the years 2010 and 2011 by the end of 2009.
- (v) As the economic scenario has undergone a major change since the time GTIPL filed its proposal in October, 2008 and considering the difficulties in finalizing a proposal at this juncture, the GTIPL likes to withdraw its proposal dated 14th October, 2008.
- (vi) To extend the validity of the existing Scale of Rates till 31 December, 2009.

4. Review of the Scale of Rates of GTIPL is already due. This Authority has already initiated a formal proceeding on the proposal filed by GTIPL in October 2008 for review of its tariff. It is, therefore, appropriate to conclude the proceedings only after hearing the concerned parties. As such, this Authority is not inclined to accede the request of

GTIPL at this juncture to withdraw its proposal dated 14th October, 2008. If it becomes necessary, the GTIPL will be afforded an opportunity to update its proposal dated 14th October, 2008 to correctly reflect the changed circumstances pointed out by it.

5. This Authority is, however, inclined to extend the validity of the existing Scale of Rates of GTIPL till 30th June, 2009 or till the effective date of implementation of the Order to be passed on the proposal of GTIPL filed by it in October, 2008, whichever is earlier.

6. Clause 2.13 of the tariff guidelines of March, 2005 will be applied to review the actual physical and financial performance of GTIPL only upto 31st December, 2008 since the estimates of financial position considered for the purpose of fixation of

estimating tariff of GTIPL in August, 2006 was till 31st December, 2008.

If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges post 1st January, 2009, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully, without reference to Clause 2.13 of the guidelines of March, 2005.

7. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority decides to extend the validity of the existing Scale of Rates of GTIPL till 30th June, 2009 or till the effective date of implementation of the Order to be passed on the proposal of GTIPL filed by it in October 2008, whichever is earlier.

ARVIND KUMAR, Member
[ADVT III/4/143/08-Exty.]